PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 029
दि. 29.05.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

कर्नाटक में बड़ा सियासी उलटफेर: सिद्धारमैया ने दिया इस्तीफा

डीके शिवकुमार के नेतृत्व में नई सरकार की अटकलें तेज

कर्नाटक की राजनीति में गुरुवार का दिन ऐतिहासिक और बेहद अहम साबित हुआ, जब लंबे समय से चल रही राजनीतिक अटकलों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों के बाद लिया गया यह फैसला राज्य की सत्ता संरचना में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। इस्तीफा राज्यपाल के सचिव को सौंपे जाने के साथ ही बेंगलुरु से लेकर नई दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई हैं।

सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास 'कावेरी' पर हुई अहम बैठक में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार सहित कई वरिष्ठ मंत्री और नेता मौजूद रहे। इस बैठक को सत्ता परिवर्तन की औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। बैठक के दौरान नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल रहा, हालांकि राजनीतिक संकेत स्पष्ट रूप से बदलाव की ओर इशारा करते नजर आए।

इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत में सिद्धारमैया भावुक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि संविधान ही उनका धर्म है और जनता उनके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि कर्नाटक की जनता ने उन्हें दो बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया, जिसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे। सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेतृत्व, विशेष रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति आभार जताया। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की स्थिरता पर कोई खतरा नहीं है और कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत मौजूद है।

राजनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम को सत्ता हस्तांतरण की योजनाबद्ध प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।

'कावेरी' आवास पर हुई बैठक की एक तस्वीर, जिसमें डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया एक-दूसरे के प्रति सम्मान दर्शाते नजर आए, सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। इसे सत्ता परिवर्तन के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में एचके पाटिल, प्रियांक खड़गे, केजे जॉर्ज, एमबी पाटिल और रामलिंगा रेड्डी जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने इस राजनीतिक बदलाव को और भी स्पष्ट कर दिया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का नाम सामने आ रहा है। पार्टी संगठन में उनकी मजबूत पकड़, चुनावी रणनीति में उनकी भूमिका और जमीनी स्तर पर उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें शीर्ष पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। उनके समर्थकों ने बेंगलुरु में उत्साह जताते हुए मिठाइयां बांटीं, जिससे यह संकेत मिला कि सत्ता परिवर्तन की दिशा लगभग तय मानी जा रही है।

हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ अंतिम दौर की बातचीत के बाद ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका इस निर्णय में निर्णायक मानी जा रही है। इस बीच कांग्रेस के भीतर प्रियांक खड़गे का नाम भी चर्चा में आ गया है। कलबुर्गी में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग ने राजनीतिक चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है। प्रियांक खड़गे युवा नेतृत्व के प्रतिनिधि के रूप में तेजी से उभरते हुए चेहरे माने जा रहे हैं और संगठन में उनकी भूमिका लगातार मजबूत हुई है। यदि कांग्रेस सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति अपनाती है, तो उन्हें भी सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अब राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के बाहर होने के कारण औपचारिक स्वीकृति और सरकार गठन की प्रक्रिया उनके लौटने के बाद पूरी की जाएगी। सिद्धारमैया ने कहा कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुसार सामान्य है और इसमें किसी तरह की अस्थिरता की बात नहीं है।

कांग्रेस के लिए यह बदलाव एक ओर राजनीतिक अवसर लेकर आया है, तो दूसरी ओर संगठनात्मक चुनौती भी प्रस्तुत करता है। हाल ही में तीन साल का कार्यकाल पूरा करने वाली कांग्रेस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि सत्ता परिवर्तन के दौरान पार्टी के भीतर कोई असंतोष न उभरे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह बदलाव सुचारू रूप से पूरा होता है, तो कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मजबूत स्थिति में आ सकती है। लेकिन यदि आंतरिक मतभेद सामने आते हैं, तो विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना सकता है।

कर्नाटक में यह घटनाक्रम केवल मुख्यमंत्री परिवर्तन भर नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में एक नए संतुलन की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। सिद्धारमैया का इस्तीफा जहां एक युग के समापन जैसा प्रतीत हो रहा है, वहीं डीके शिवकुमार के नेतृत्व में संभावित नई सरकार एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रही है।

आने वाले दिनों में कांग्रेस हाईकमान की ओर से होने वाली आधिकारिक घोषणा यह तय करेगी कि कर्नाटक की कमान वास्तव में किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल राज्य की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां हर कदम भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित होगा और सभी की निगाहें दिल्ली में होने वाले अंतिम निर्णय पर टिकी हुई हैं।

तमिलनाडु की सियासत में हलचल: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का दिल्ली दौरा समाप्त, कांग्रेस नेतृत्व से दूरी ने बढ़ाई राजनीतिक चर्चा

नई दिल्ली/चेन्नई में गुरुवार को उस समय राजनीतिक चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय अपनी पहली आधिकारिक दिल्ली यात्रा पूरी कर चेन्नई लौट आए। यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि इसे राज्य और केंद्र के बीच संबंधों, विभिन्न लंबित मुद्दों और राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा था। हालांकि, इस यात्रा में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात ने खींचा कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेतृत्व से कोई औपचारिक मुलाकात नहीं की, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का यह दौरा मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रमों और केंद्र सरकार के साथ आधिकारिक बातचीत तक ही सीमित रहा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर तमिलनाडु से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इनमें मेकेदातु बांध विवाद, राज्य के मछुआरों की सुरक्षा और गिरफ्तारी से जुड़े मामले तथा तमिल वंदना गीत को लेकर उठे

विवाद जैसे संवेदनशील विषय शामिल रहे। बैठक को दोनों पक्षों के बीच औपचारिक और मुद्दा-केंद्रित बताया जा रहा है।

हालांकि, इस यात्रा का सबसे चर्चित पहलू कांग्रेस नेतृत्व, विशेष रूप से राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात न होना रहा। कांग्रेस सांसद क्रिस्टोफर तिलक ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मुलाकात इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि मुख्यमंत्री की यह यात्रा पूरी तरह सरकारी और प्रशासनिक कार्यक्रमों तक सीमित थी, न कि किसी राजनीतिक संवाद के लिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुलाकात रद्द नहीं हुई है, बल्कि इसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है।

तिलक ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री आगामी 11 जून के आसपास नीति आयोग की बैठक के लिए एक बार फिर दिल्ली आ सकते हैं। उस समय राजनीतिक मुलाकातों की संभावना भी बन सकती है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ औपचारिक बातचीत हो सकती है। इस बयान के बाद यह संकेत मिला कि कांग्रेस और तमिलनाडु नेतृत्व के बीच संवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह केवल समय और परिस्थितियों पर निर्भर है।

इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में केंद्र और विपक्षी दलों के बीच संबंध हमेशा से रणनीतिक महत्व रखते हैं। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब राज्य में विकास परियोजनाओं, केंद्र से फंडिंग और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर कई स्तरों पर बातचीत की आवश्यकता बनी हुई है। ऐसे में केवल प्रधानमंत्री से मुलाकात और कांग्रेस नेतृत्व से दूरी ने कई तरह की राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह रहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के साथ सीधे संवाद को प्राथमिकता दी, जबकि विपक्षी दलों के साथ औपचारिक राजनीतिक बातचीत से फिलहाल दूरी बनाए रखी। हालांकि इसे पूरी तरह राजनीतिक दूरी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह निश्चित रूप से एक रणनीतिक संतुलन का संकेत माना जा रहा है।

चेन्नई लौटने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि यह यात्रा पूरी तरह प्रशासनिक एजेंडे पर आधारित थी और इसका उद्देश्य केवल राज्य से जुड़े लंबित मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ चर्चा करना था। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में आवश्यकतानुसार सभी राजनीतिक और प्रशासनिक स्तरों पर संवाद जारी रहेगा।

इस बीच, मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है, जिसे तमिलनाडु सरकार लगातार गंभीरता से उठाती रही है।

ईडी छापेमारी के बाद केरल की सियासत गरमाई, कांग्रेस का पलटवार-पूर्व सीएम पिनारयी विजयन पर उठाए तीखे सवाल

तिरुवनंतपुरम में राजनीतिक तापमान एक बार फिर बढ़ गया है, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के बाद केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता पिनारयी विजयन के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। ईडी द्वारा कथित वित्तीय लेनदेन मामले में छापेमारी किए जाने के बाद जिस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आईं, उसने राज्य की राजनीति को केंद्र और विपक्ष के बीच नए टकराव के मोड़ पर ला खड़ा किया है। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विजयन के रवैये पर सवाल उठाए हैं और उन्हें केंद्र सरकार के बजाय विपक्षी दलों पर हमला करने का आरोप लगाया है।

ईडी की कार्रवाई के तुरंत बाद पिनारयी विजयन ने बयान दिया था कि "राहुल गांधी अब खुश होंगे", जो सीएमआरएल-एक्सालॉजिक वित्तीय लेनदेन मामले में ईडी द्वारा उनकी ओर से किसी बड़ी कार्रवाई न किए जाने को लेकर कांग्रेस द्वारा पहले उठाए गए सवालों की ओर संकेत करता है। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में तुरंत प्रतिक्रिया पैदा कर दी और कांग्रेस ने इसे गंभीरता से लेते हुए पलटवार किया।

केरल के राजस्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.पी. अनिल कुमार ने इस मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री का फोकस केंद्र सरकार पर सवाल उठाने के बजाय राहुल गांधी पर हमला करने की ओर चला गया, जो हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब किसी नेता के आवास पर केंद्रीय एजेंसी छापेमारी करती है, तो स्वाभाविक रूप से सवाल केंद्र सरकार की नीतियों और एजेंसियों की भूमिका पर उठने चाहिए, लेकिन विजयन का रुख इसके विपरीत दिखाई दिया।

अनिल कुमार ने सवाल उठाया कि पिनारयी विजयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर सीधा हमला करने से क्यों बचते हैं। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किसी मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जाती है, तो उस पर राजनीतिक जवाबदेही तय करने की आवश्यकता होती है, लेकिन विजयन का बयान इस दिशा में नहीं गया। इसके बजाय उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाया, जो राजनीतिक रूप से एक अलग संदेश देता है।

कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि पिनारयी विजयन का रवैया केंद्र सरकार के प्रति नरम और विपक्षी नेताओं के प्रति आक्रामक रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक विशेष प्रकार की सावधानी या भय दिखाया है, और यह बात उनके हालिया बयान से एक बार फिर स्पष्ट हो गई है। अनिल कुमार के अनुसार, इस तरह के बयान राजनीतिक बहस को मुद्दों से भटकाकर व्यक्तिगत आरोपों की ओर ले जाते हैं। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब केरल की राजनीति पहले से ही कई प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर संवेदनशील बनी हुई है। ईडी की छापेमारी ने राज्य में राजनीतिक सरगर्मी को और बढ़ा दिया है और विपक्ष तथा सत्ताधारी दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, जबकि सीपीएम और पिनारयी विजयन खेमे का कहना है कि जांच प्रक्रियाएं कानून के दायरे में हो रही हैं और इन्हें राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।

पिनारयी विजयन द्वारा दिए गए बयान और उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया ने राज्य की राजनीति को एक बार फिर केंद्र बनाम विपक्ष के नैरेटिव में ला खड़ा किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान और पलटवार केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यह आगामी राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि अगर किसी भी नेता के खिलाफ जांच होती है, तो उसका जवाब राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाना चाहिए।

टीएमसी में बड़ा राजनीतिक भूचाल: राष्ट्रीय प्रवक्ता शांतनु सेन का इस्तीफा, आरजी कर विवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों से बढ़ी हलचल

र बदलते राजनीतिक माहौल को समझते हुए वह टीएमसी के अखिल भारतीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी से अनुरोध किया कि उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाए और उनके निर्णय का सम्मान किया जाए। उनके इस बयान को सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व के प्रति असंतोष और मौजूदा संगठनात्मक कार्यशैली पर सवाल के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक हलकों में शांतनु सेन का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे लंबे समय से टीएमसी के उन नेताओं में शामिल थे जो मीडिया में पार्टी का आक्रामक तरीके से बचाव करते थे। एक प्रवक्ता के रूप में उनकी पहचान काफी मजबूत रही है और वे कई बार राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की आवाज बने। ऐसे में उनके इस्तीफे को केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों का संकेत माना जा रहा है।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज विवाद और उससे जुड़े प्रदर्शन पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले ही संवेदनशील मुद्दा बने हुए हैं। इस मामले ने राज्य की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए थे। इसी तरह 'कैश फॉर जॉब' जैसे आरोपों ने भी राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया था। शांतनु सेन द्वारा इन घटनाओं का उल्लेख करना इस बात का संकेत देता है कि वे इन मुद्दों को लेकर पार्टी की मौजूदा स्थिति से सहमत नहीं थे।

टीएमसी के भीतर यह इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब पार्टी पहले से ही विपक्षी दलों के तीखे हमलों का सामना कर रही है। विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का सार्वजनिक रूप से असंतोष जताना और इस्तीफा देना राजनीतिक रूप से एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

हालांकि टीएमसी की ओर से इस इस्तीफे पर अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी इस घटनाक्रम को संगठनात्मक स्तर पर आंतरिक मुद्दे के रूप में संभालने की कोशिश करेगी। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर इस पर और चर्चाएं तेज हो सकती हैं।

शांतनु सेन के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत ईमानदारी और साहसिक कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक असंतोष और पार्टी के भीतर बढ़ती खींचतान का परिणाम मान रहे हैं। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले समय में नए समीकरणों को जन्म दे सकती है।

टीएमसी के लिए यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब पार्टी राज्य में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीतियों पर काम कर रही है। ऐसे में एक वरिष्ठ प्रवक्ता का इस्तीफा निश्चित रूप से पार्टी की छवि और अंदरूनी स्थिति पर सवाल खड़े करता है।

फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी नेतृत्व इस इस्तीफे पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या शांतनु सेन आगे किसी नए राजनीतिक मंच की ओर रुख करते हैं या फिर यह फैसला केवल मौजूदा परिस्थितियों तक ही सीमित रहता है। लेकिन इतना तय है कि इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसका असर आने वाले समय में और गहराता दिखाई दे सकता है।

शहरी बुनियादी ढांचा पर्यावरण अनुकूल व मानवीय बने

संपादकीय

मूल्यांकन पर आंच

अभी नीट प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्रों के लीक होने और परीक्षा रद्द होने की सुर्खियों की स्याही सूखी भी न थी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली सवालों के घेरे में आ गई। निश्चय ही ये घटनाक्रम छात्रों और प्रतियोगियों के परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे को कम ही कर रहे हैं। आपदा में अवसर की तलाश में रहने वाले राजनीतिक दलों को छोड़ भी दें, तो भी आम लोग भी सीबीएसई की मूल्यांकन पद्धति पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल, सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली में खामियों और विसंगतियों को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं। कक्षा बारह के कुछ छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत अपलोड की गई स्कैन प्रतियों और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में विसंगति सामने आने का खुलासा किया है। निश्चित रूप से यह प्रकरण महज एक तकनीकी समस्या से कहीं अधिक का मामला है। यह भारत की उस शीर्ष परीक्षा प्रणाली की बढ़ती विफलता की चेतावनी है, जो लाखों छात्रों के भविष्य का निर्धारण करती है। इस घटनाक्रम में एक छात्र वेदांत श्रीवास्तव का मामला विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि सीबीएसई ने स्वयं स्वीकार किया है कि गलत उत्तर पुस्तिका भेजी गई थी। हालांकि, मामला तूल पकड़ता देख उसे बाद में सही उत्तर पुस्तिका भेज दी गई। इसी तरह एक अन्य परीक्षार्थी, संजना को भी सीबीएसई की तरफ से कमोबेश ऐसी ही प्रतिक्रिया मिली है। भला हो सोशल मीडिया का जो इन मुद्दों को देश की जनता के सामने तुरंत ले आता है और देश में इससे एक जनमत बनाने का अवसर मिलता है। हालांकि, यह स्वागत योग्य है कि सीबीएसई ने इन प्रणालीगत त्रुटियों को स्वीकार तो किया। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस लापरवाही के लिये जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा लापरवाही व गलती का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सीबीएसई को अपनी साख बचाये रखने के लिये इस दिशा में समय रहते सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

यहां सवाल उठता है कि सीबीएसई जैसी परीक्षा नियामक संस्था ने अपने स्तर पर खामियों को दूर करने के लिये कारगर तंत्र क्यों विकसित नहीं किया। वह तब ही जागती है जब मीडिया में घटना सुर्खियां बनती है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सीबीएसई ने तब कार्रवाई की और सुधारात्मक कदम उठाये, जब प्रभावित छात्रों ने इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। निश्चित रूप से एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली में इतना लचीलापन होना चाहिए कि छात्रों के आक्रोश के सार्वजनिक होने, राजनीतिक टीका-टिप्पणी सामने आने या ऑनलाइन अभियान चलने से पहले समस्या का निराकरण हो जाए। हालिया घटनाक्रम का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि सीबीएसई की लापरवाही का शिकार बने वेदांत को अपनी बात उठाने पर बुरी तरह लांछित किया। कुछ सोशल मीडिया वीरों ने उसकी मुखरता से आवाज उठाने की कोशिश को देश विरोधी तक ही नहीं कहा, बल्कि कुछ ने तो उसे पाकिस्तानी तक कह दिया। यह तंत्र के बचाव में उतरने की अंधभक्ति ही है कि न्याय के लिये आवाज उठाने के लिये पीड़ित भारतीय नागरिक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की असफल कोशिश हो। क्या न्याय के लिये आवाज उठाने वाले छात्रों को इसलिए अपमानित व प्रताड़ित होना चाहिए क्योंकि उसकी शिकायत सामने आने के बाद देश के नामचीन संगठनों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है? वास्तव में इन छात्रों के मामले में आई खामियों की व्यापक स्तर पर पड़ताल होनी चाहिए। यह भी विचार करना चाहिए कि कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना आनन-फानन में डिजिटलीकरण कराने से ही कहीं ऐसी खामियां तो सामने नहीं आ रही हैं? निश्चित रूप से इसका खमियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ता है और उनका भविष्य दांव पर लग जाता है। यह हकीकत है कि सीबीएसई का भूल सुधार करने का प्रयास कभी व्यवस्थागत सुधार का विकल्प नहीं हो सकता। बोर्ड को तत्काल ओएसएम प्रणाली और स्कैनिंग प्रक्रियाओं का स्वतंत्र ऑडिट कराना चाहिए। परीक्षा बोर्ड और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियां योग्यता और निष्पक्षता की संरक्षक मानी जाती हैं। सवालों से घिरी भारतीय शिक्षा प्रणाली तभी अपनी विश्वसनीयता बचा सकती है, जब वह बुनियादी प्रक्रियात्मक विश्वसनीयता की गारंटी देने का वायदा करे।

> "आईसीएमआर और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टें सचेत कर रही हैं कि अत्यधिक गर्मी और लगातार अधूरी नींद इंसानी शरीर के भीतर तापमान नियंत्रित करने की क्षमता को नष्ट कर देती है। जब लगातार कई दिनों तक इंसान की नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर में तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन 'कोर्टिसोल' अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है।

जेठ की तपती दोपहरी में जब पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, तो महानगरों की आलीशान इमारतों के पीछे छिपा एक डरावना और कड़वा सच बाहर आने लगता है। दिनभर की हाड़-तोड़ मेहनत और चिलचिलाती धूप का सामना करने के बाद जब एक आम कामकाजी इंसान शाम को अपने घर लौटता है, तो उसे कुछ पल के सुकून और चैन की नींद की उम्मीद होती है। लेकिन आधुनिकता और अनियंत्रित विकास के दौर में हमारे महानगर रहने लायक ठिकाने कम और 'तपते तवे' अधिक बन चुके हैं। बुनियादी ढांचे का चरमराना, 'अर्बन हीट आइलैंड' का बढ़ता प्रभाव, पानी का गंभीर संकट और उस पर से बेहिसाब बिजली कटौती ने इंसान के जीवन को एक दुःस्वप्न में बदल दिया है। संकट अब शारीरिक थकावट या पसीने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें गंभीर रूप से शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार बना रहा है।

मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद धरती ठंडी होती है और रातें सुकून देती हैं। लेकिन हमारे महानगरों में यह प्राकृतिक चक्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, जिसका मुख्य कारण 'अर्बन हीट आइलैंड' का प्रभाव है। जब किसी शहर में पेड़-पौधों, तालाबों और खुली जमीनों को बेरहमी से खत्म करके वहां डामर की सड़कें, कंक्रीट की बहुमंजिला इमारतें और कांच के शीशों से ढके टॉवर खड़े कर दिए जाते हैं, तो वे दिनभर सूरज की भीषण गर्मी को अपने भीतर सोख लेते हैं। रात के समय, जब तापमान कम होना चाहिए, ये कंक्रीट के ढांचे उस सोखी हुई गर्मी को वापस वातावरण में छोड़ना शुरू करते हैं। 'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' के वैज्ञानिक अध्ययन पुष्टि करते हैं कि महानगरों में रात का तापमान ग्रामीण या खुले इलाकों की तुलना में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज हो रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि महानगरों में रातें

अब दिनों से भी ज्यादा भारी और उमस भरी हो रही हैं।

इस भयंकर रात की उमस में जब 'पावर कट' या बिजली कटौती का झटका लगता है, तो नागरिक पूरी तरह असहाय हो जाता है। इन्वर्टर कुछ घंटों में दम तोड़ देते हैं, पानी की मोटरें शांत हो जाती हैं और हवा का नामोनिशान मिट जाता है। आईसीएमआर और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टें सचेत कर रही हैं कि अत्यधिक गर्मी और लगातार अधूरी नींद इंसानी शरीर के भीतर तापमान नियंत्रित करने की क्षमता को नष्ट कर देती है। जब लगातार कई दिनों तक इंसान की नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर में तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन 'कोर्टिसोल' अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है। यही कारण है कि लोग 'एक्यूट' यानी गंभीर और अचानक उभरने वाली बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन ओपीडी के आंकड़े बताते हैं कि मई-जून के महीनों में हीट स्ट्रोक, अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्रेन स्ट्रोक, गंभीर डिहाइड्रेशन और किडनी फेलियर के मामलों में एक-तिहाई से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है। जब पानी का अभाव और अगले दिन बिना सोए दफ्तर या काम पर जुटने की चिंता जुड़ती है, तो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है।

संकट का सबसे भयावह और मूक पहलू महानगरों में मानसिक रोगियों की बढ़ती फौज है। गर्मी और बिजली संकट को अक्सर हम केवल एक भौतिक या प्रशासनिक समस्या मानते हैं, लेकिन यह सीधे तौर पर हमारी मानसिक सुदृढ़ता पर हमला कर रहा है। 'द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ' में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, तापमान में प्रति एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अवसाद के मामलों में दो प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी होती है। लगातार अनिद्रा और शारीरिक कष्ट के कारण लोग गंभीर चिड़चिड़ेपन, घबराहट और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का शिकार हो रहे हैं। अत्यधिक गर्मी से उसकी मानसिक सहनशीलता समाप्त हो जाती है। महानगरों में घरेलू हिंसा, सड़कों पर मामूली बात पर होने वाली 'रोड रेज' की हिंसक घटनाएं और दफ्तरों में कर्मचारियों के बीच बढ़ते टकराव के पीछे इस 'थर्मल स्ट्रेस' का बहुत बड़ा हाथ है। मनोचिकित्सकों के अनुसार, इन दिनों ओपीडी में आने वाले हर पांचवें मरीज में अनिद्रा और गर्मी जनित मानसिक तनाव मुख्य कारण बनकर उभर रहा है।

यह स्थिति हमारी नीतिगत विफलताओं का आईना है। गर्मियों के दिनों में महानगरों के उपनगरों और रिहायशी सोसायटियों में हाहाकार मचा रहता है। ट्रांसफार्मर फुंकने और केबल जलने की घटनाएं आम हैं क्योंकि बिजली के बुनियादी ढांचे पर क्षमता से अधिक लोड है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए एसी और कूलर चलाने को मजबूर है, लेकिन हमारा वितरण ग्रिड इस मांग को संभालने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अमीर वर्ग तो भारी-भरकम डीजल जनरेटरों के सहारे कुछ राहत पा लेता है, जो खुद प्रदूषण बढ़ाकर हवा को और गर्म करते हैं, लेकिन मध्यम और निम्न वर्ग के लोग कंक्रीट के छोटे-छोटे कमरों में 'तंदूर' की तरह पकने को मजबूर हैं। पानी के टैंकरों के पीछे लगती लंबी लाइनें और पानी के लिए होते झगड़े प्रमाण हैं कि नगरीय ढांचा चरमरा चुका है।

यदि हमें अपने शहरों को बीमारों का घर बनने से रोकना है, तो पारंपरिक सोच से हटकर नए और साहसिक कदम उठाने होंगे। प्रशासन को चाहिए कि दिन के बजाय रात के समय आवासीय परिसरों और कॉलोनियों की सड़कों पर स्प्रिंकलर ट्रकों को लगातार चलाए। इससे 'अर्बन हीट आइलैंड' के प्रभाव को सीधे तौर पर कम किया जा सकता है। इससे डामर और कंक्रीट द्वारा सोखी गई गर्मी शांत होगी, जिससे रात के तापमान में गिरावट से कुछ राहत मिल सकेगी।

इसके साथ ही, शहरी नियोजन में 'व्हाइट रूफिंग' को बढ़ावा देना होगा और बिजली वितरण प्रणाली को सौर ऊर्जा के ग्रिड से जोड़कर मजबूत करना होगा ताकि ग्रिड फेल होने की नौबत न आए। बिजली, पानी और ठंडी हवा अब कोई विलासिता नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में शहरों के बुनियादी ढांचे को पर्यावरण के अनुकूल और मानवीय बनाना होगा।

प्रेरणा

जब इंसान खुद अपना बोझ बन जाता है

बहुत समय पहले की बात है। रेगिस्तान के किनारे बसे एक छोटे से इलाके में बाबा कमरुद्दीन नाम के एक फ़क़ीर रहते थे। लोग कहते थे कि उनके पास ऐसी समझ थी, जो टूटे हुए दिलों को भी सुकून दे देती थी। उनके दरवाजे पर अमीर-गरीब, राजा-फकीर सब आते थे। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई अपनी परेशानियां, तो कोई अपने मन की बेचैनी। बाबा ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी छोटी-छोटी बातें लोगों की जिंदगी बदल देती थीं।

एक दिन दूर शहर से एक बहुत बड़ा सौदागर उनके पास पहुंचा। उसके साथ कई नौकर थे। ऊंटों पर कीमती सामान लदा हुआ था। उसके कपड़े इतने महंगे थे कि आम आदमी उन्हें छूने की भी हिम्मत न करे। उसकी उंगलियों में हीरे-जवाहरात चमक रहे थे। बाहर से देखने पर वह आदमी बेहद खुश और सफल लगता था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी थकान थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं।

वह बाबा के सामने बैठा और भारी आवाज़ में बोला, "बाबा, मेरे पास सब कुछ है। बड़ा कारोबार है, कई हवेलियां हैं, नौकर-चाकर हैं, लोग सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिल को चैन नहीं मिलता। मैं हर वक्त परेशान रहता हूं। रात को नींद नहीं आती। मन हमेशा डरा रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर सुकून कहां मिलता है?"

बाबा कमरुद्दीन ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर बिना कुछ कहे पास पड़ा एक बड़ा बोरा उठाया। उस बोरे में कई भारी पत्थर भरे हुए थे। उन्होंने वह बोरा सौदागर के कंधे पर रख दिया और बोले, "इसे उठाओ और मेरे साथ चलो।"

सौदागर को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। वह बोरा उठाकर बाबा के पीछे चल पड़ा। शुरुआत में उसे लगा कि यह कोई मामूली काम है। आखिर वह ताकतवर और स्वस्थ आदमी था। लेकिन जैसे-जैसे वे रेगिस्तान की ओर बढ़ते गए, धूप तेज़ होती गई। गर्म हवाएं शरीर को झुलसाने लगीं। पैरों के नीचे की रेत आग जैसी तप रही थी।

कुछ दूर चलने के बाद सौदागर के कंधे दर्द से भर गए। बोरे का वजन उसे भारी लगने लगा। उसका गला सूख गया। माथे से लगातार पसीना बहने लगा। उसने हांफते हुए कहा, "बाबा, यह बोझ बहुत भारी है।"

बाबा ने शांत स्वर में जवाब दिया, "थोड़ा और चलो।"

सौदागर ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा, लेकिन अब हर कदम उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसे लग रहा था जैसे उसकी ताकत खत्म होती जा रही है। कुछ दूर और चलने के बाद वह अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज़ चल रही थीं। उसने दर्द से भरी आवाज़ में कहा, "अब नहीं चला जाता बाबा। यह बोझ मेरी जान निकाल देगा।"

तब बाबा उसके पास आए और बोले, "बोरा नीचे रख दो।"

सौदागर ने तुरंत बोरा जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वजन उसके कंधों से उतरा, उसने राहत की लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर हल्का हो गया हो। कुछ क्षण पहले जो रास्ता उसे असहनीय लग रहा था, वही अब आसान महसूस होने लगा।

बाबा उसके सामने बैठ गए और बोले, "जिस तरह यह बोरा तुझे थका रहा था, उसी तरह तेरे भीतर जमा डर, लालच, घमंड और पुरानी शिकायतें तुझे हर दिन थका रही हैं। इंसान बाहर से जितना अमीर होता जाता है, भीतर उतना ही भारी होता जाता है।"

सौदागर चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। बाबा ने रेत की एक मुट्ठी उठाई और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। फिर बोले, "इंसान हर चीज़ को पकड़कर रखना चाहता है। धन, इज्जत, रिश्ते, गुस्सा, बदला—सब कुछ। उसे डर रहता है कि कहीं कुछ छूट न जाए। लेकिन जितना वह पकड़ता है, उतना ही दुखी होता जाता है।"

फिर उन्होंने धीरे-धीरे अपनी मुट्ठी खोल दी। रेत नीचे गिरने लगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, "देखा? जब हाथ खुल जाता है, तो रेत भी गिर जाती है और हाथ भी हल्का हो जाता है। जिंदगी में सुकून पाने के लिए पकड़ना नहीं, छोड़ना सीखना पड़ता है।" सौदागर की आंखें झुक गईं। उसे लगा जैसे बाबा उसकी जिंदगी का सच उसके सामने रख रहे हों। उसने सारी उम्र सिर्फ कमाने में बिताई थी। उसे हमेशा और ज्यादा चाहिए था। अगर उसके पास एक हवेली होती, तो वह दूसरी बनवाने की सोचता। अगर कारोबार बढ़ता, तो उसे खोने का डर बढ़ जाता। अगर लोग उसकी तारीफ करते, तो वह चाहता कि पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करे। इसी चाहत ने उसके भीतर का चैन छीन लिया था। बाबा ने कहा, "दुनिया की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग सोचते हैं ज्यादा पाने से खुशी मिलेगी। लेकिन खुशी ज्यादा इकट्ठा करने से नहीं, अनावश्यक बोझ हटाने से मिलती है। जिस दिल में नफरत और डर भरा हो, वहां सुकून कभी नहीं ठहरता।"

रेगिस्तान में धीरे-धीरे शाम उतरने लगी थी। सूरज की लाल रोशनी रेत पर फैल रही थी। हवा अब थोड़ी ठंडी हो चुकी थी। सौदागर पहली बार उस सन्नाटे को महसूस कर रहा था, जिसमें अजीब सा सुकून था।

उसने धीरे से पूछा, "लेकिन बाबा, इंसान छोड़ना कैसे सीखे? पुरानी बातें दिल से निकलती ही नहीं।"

बाबा ने मुस्कुराकर कहा, "जैसे पेड़ पतझड़ में अपने सूखे पत्ते गिरा देता है। अगर वह पुराने पत्तों को पकड़े रहे, तो नए पत्ते कभी नहीं उगेंगे। वैसे ही इंसान को भी पुराने दुख, अपमान और शिकायतें छोड़नी पड़ती हैं। जब तक दिल पुरानी चीज़ों से भरा रहेगा, उसमें नई रोशनी नहीं आएगी।"

सौदागर अब पूरी तरह शांत होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी बाहर की नहीं, भीतर की थी। वह दुनिया से नहीं, खुद से हार चुका था। उसका मन हमेशा डर और लालच के बीच फंसा रहता था। इसी वजह से उसके पास सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं था।

बाबा ने कहा, "याद रखो, जिंदगी में इंसान को सबसे ज्यादा थकाने वाला रास्ता नहीं होता, बल्कि वह बोझ होता है जिसे वह बेवजह उठाए फिरता है। कुछ लोग उम्र भर शिकायतों का बोरा उठाते रहते हैं। कुछ लोग अहंकार का। कुछ लोग डर का। फिर वे सोचते हैं कि उन्हें खुशी क्यों नहीं मिलती।" सौदागर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि असली गरीबी पैसे की नहीं, मन की होती है। जिस इंसान का दिल अशांत हो, वह लाख दौलत के बाद भी गरीब ही रहता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की सफल यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे और इटली की छह दिवसीय यात्रा संपन्न हो चुकी है। पश्चिमी एशिया संकट सहित दुनियाभर में चल रही उथल-पुथल तथा चीन की विस्तारवादी नीतियों के दृष्टिगत प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इन देशों से द्विपक्षीय संबंध सुधारने की दिशा में एक अहम पड़ाव बनी। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान उन्हें स्वीडन तथा नार्वे जैसे देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर सम्मानित किया। नार्वे की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-नार्डिक देशों के शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा के दौरान कुल 57 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ हैं। इन यात्राओं का एक परोक्ष संदेश यह भी है अब भारत दुनिया के ताकतवर देशों की कूटनीति की छत्रछाया से बाहर निकल कर अपनी स्वतंत्र नीति पर चल रहा है। यूएई की यात्रा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के प्रथम चरण में यूएई पहुंचे। यहाँ भारत और यूएई के मध्य सात समझौते हुए। इन समझौतों के अंतर्गत भारत व यूएई में संयुक्त तौर पर पेट्रो उत्पादों के रणनीतिक भंडार बनाए जाएंगे। यूएई भारत में दीर्घकालिक तौर पर एलपीजी आपूर्ति करेगा, पांच अरब डॉलर का नया निवेश करके भारत में सुपर कंप्यूटर क्लस्टर स्थापित करेगा। एक समझौता गुजरात के वाडीनार में शिप रिपेयरिंग क्लस्टर बनाने को लेकर भी है। इससे लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। दोनो देशों की कंपनियां मिलकर बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर प्रणाली स्थापित करेंगी जो एआई ट्रेनिंग, रिसर्च और बड़े-बड़े मॉडल चालने के लिए प्रयोग की जाएगी। दोनों देशों के बीच रक्षा, औद्योगिक सहयोग, नवाचार उन्नत प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास शिक्षा एवं सैन्य डॉक्ट्रिन, विशेष अभियान, अंतर-संचालन क्षमता, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सुरक्षित संचार और सूचना आदान प्रदान के लिए एक व्यापक रणनीतिक ढांचा स्थापित करने की सहमति बनी है। नीदरलैंड- अपनी यात्रा के अगले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड पहुंचे जहां उनका भव्य व गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। भारत और नीदरलैंड के मध्य 17 द्विपक्षीय समझौतों से एक नया रिकॉर्ड बना। भारत और नीदरलैंड व्यापार और निवेश रक्षा और सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जे टेन के मध्य हूई वार्ता के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में 17 समझौते हुए। हरित हाइड्रोजन के विकास पर सहमति के साथ दोनों देश संयुक्त रक्षा उपकरण प्रणाली घटकों और अन्य प्रमुख क्षमताओं के संयुक्त निर्माण के लिए रक्षा औद्योगिक रोडमैप स्थापित करने की संभावनाओं का भी पता लगाएंगे। इसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त उद्यमों की स्थापना शामिल है।

संयुक्त बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने विज्ञान और नवाचार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण, समुद्री विकास और जन संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। आव्रजन मोबिलिटी पर भी समझौता हुआ। इसके अंतर्गत कुशल भारतीय पेशवेरों के लिए नीदरलैंड में काम करने की प्रक्रियाओं को आसान व निष्पक्ष बनाया जाएगा। अवैध प्रवासन रोकने के लिए भी सहमति बनी है। नीदरलैंड के पास पानी के प्रबंधन की बेहतरीन तकनीक है जिसमें भारत के साथ सहयोग मजबूत होगा। समझौतों से अर्धचालक, अहम खनिज, स्वास्थ्य, जल, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि व संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। इस दौरे की एक बड़ी बात यह रही कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जेटेन ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगात आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अटूट समर्थन का भरोसा दिया। स्वीडन- प्रधानमंत्री नरेंद मोदी अपनी यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन पहुंचे जहां एयरपोर्ट पर स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान "रॉयल ऑर्डरऑफ़ पोलर स्टार" से सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी का 31 वां सम्मान है। भारत-स्वीडन संबंधों में प्रधानमंत्री मोदी के असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक व्यापार को बढ़ाने सहित व्यापक अवसरों और निवेश को बढावा देने पर चर्चा की।

नार्वे- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नार्वे यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्षों के अंतराल के बाद की जाने वाली नार्वे यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नार्वे के शहर ओस्लो में भारत-नार्डिक शिखर सम्मलेन में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नार्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान "ग्रैंड क्रास ऑफ़ द रॉयल नार्वेजियन आर्डर ऑफ़ मेरिट" से सम्मनित किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 32 वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। भारत और नार्वे के बीच ग्रीन एनर्जी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझौते पर सहमति बनी।नार्वे के साथ स्वास्थ्य और डिजिटल तकनीक क्षेत्र में भी समझौते हुए।

अभियान

मनोकामनाओं की देवी: जहां मां मनसा भर देती हैं सूनी गोद और अधूरी जिंदगी में आस्था का प्रकाश

देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही देवताओं की धरती नहीं कहा जाता। हिमालय की गोद में बसा यह पवित्र प्रदेश अपने भीतर हजारों वर्षों की आध्यात्मिक परंपरा, चमत्कारिक कथाएं और अटूट आस्था समेटे हुए है। यहां का हर पर्वत, हर नदी और हर मंदिर अपने भीतर कोई न कोई दिव्य रहस्य छिपाए बैठा है। इन्हीं पावन स्थलों में से एक है हरिद्वार के बिल्व पर्वत पर स्थित मां मनसा देवी का मंदिर, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ मां के दरबार में आता है, वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। किसी को संतान सुख मिलता है, किसी के जीवन में सुख-शांति आती है, तो किसी की वर्षों पुरानी अधूरी इच्छा यहां पूरी हो जाती है।

हरिद्वार को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। गंगा के तट पर बसा यह शहर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि आस्था और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इसी पावन नगरी के बिल्व पर्वत पर मां मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यह मंदिर इतनी ऊंचाई पर बना है कि यहां पहुंचते ही श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होता है मानो वे सांसारिक जीवन की भागदौड़ से दूर किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर चुके हों। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु पैदल चढ़ाई करते हैं या फिर रोपवे की सहायता लेते हैं। जैसे-जैसे भक्त ऊपर पहुंचते हैं, वैसे-वैसे हरिद्वार का अद्भुत दृश्य और गंगा की पवित्र धारा मन को आध्यात्मिक शांति से भर देती है।

मां मनसा देवी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार "मनसा" शब्द की उत्पत्ति "मनसा" यानी मन की इच्छा से हुई है। ऐसा कहा जाता है कि मां मनसा अपने भक्तों के मन की हर इच्छा जान लेती हैं और सच्ची श्रद्धा से मांगी गई मुराद अवश्य पूरी करती हैं। यही कारण है कि इस मंदिर को मनोकामना पूर्ण करने वाला सिद्धपीठ कहा जाता है। यहां आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में पवित्र धागा बांधते हैं और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो वे दोबारा आकर उस धागे को खोलते हैं। वर्षों से चली आ रही यह परंपरा आज भी भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है।

मां मनसा देवी मंदिर का इतिहास भी बेहद रोचक और रहस्यमयी माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1811 से 1815 के बीच राजा गोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान की महिमा उससे भी कहीं अधिक प्राचीन है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ था, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर जिन स्थानों पर गिरी थीं, उनमें हरिद्वार भी शामिल था। यही कारण है कि हरिद्वार को कुंभ नगरी कहा जाता है और यहां स्थित मां मनसा देवी का मंदिर अत्यंत पवित्र माना जाता है।

मंदिर में स्थापित मां मनसा देवी की प्रतिमाएं भी श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। यहां मां की दो प्रमुख मूर्तियां विराजमान हैं। पहली प्रतिमा के तीन मुख और पांच भुजाएं हैं, जबकि दूसरी प्रतिमा में मां आठ भुजाओं के साथ सर्प पर विराजमान दिखाई देती हैं। मां का यह स्वरूप शक्ति, करुणा और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। भक्त जब इन दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, तो उनके भीतर असीम श्रद्धा और विश्वास जाग उठता है।

इस मंदिर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध मान्यता संतान प्राप्ति को लेकर है। कहा जाता है कि जो दंपति संतान सुख से वंचित होते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ मां मनसा देवी के दरबार में आकर प्रार्थना करते हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। देश के अलग-अलग हिस्सों से हजारों दंपति यहां केवल इसी आस्था के साथ आते हैं। कई भक्त ऐसे भी मिल जाते हैं, जो बताते हैं कि वर्षों तक संतान न होने के बाद मां मनसा देवी की कृपा से उनकी गोद भर गई। यही वजह है कि यह मंदिर निःसंतान दंपतियों के लिए विशेष आस्था का केंद्र बन चुका है।

इतना ही नहीं, सुहागिन महिलाएं भी यहां अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए विशेष पूजा-अर्चना करती हैं। नवरात्रि और सावन के दिनों में यहां महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। लाल चुनरी, नारियल और फूल लेकर आने वाली महिलाएं मां से अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। मंदिर परिसर में गूंजते जयकारे और घंटियों की ध्वनि वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना देती है।

हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मां मनसा देवी के दर्शन अधूरे नहीं माने जाते। कहा जाता है कि हरिद्वार की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती, जब तक श्रद्धालु मां मनसा देवी और मां चंडी देवी के दर्शन न कर लें। यही कारण है कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। विशेष रूप से चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान यहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। मंदिर को रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। दूर-दूर तक "जय मां मनसा" के जयकारे सुनाई देते हैं और पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठता है।

मंदिर के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। बिल्व पर्वत से दिखाई देने वाला हरिद्वार का दृश्य बेहद मनमोहक लगता है। नीचे बहती गंगा, दूर तक फैले मंदिरों के शिखर और पहाड़ों की हरियाली मन को अद्भुत शांति प्रदान करती है। कई श्रद्धालु यहां केवल दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति पाने के लिए भी आते हैं। कहा जाता है कि मां के दरबार में कुछ देर बैठने मात्र से मन की बेचैनी दूर होने लगती है।

धार्मिक दृष्टि से मां मनसा देवी को नागों की देवी भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुई थीं। यही कारण है कि उनका संबंध शिव शक्ति परंपरा से भी जोड़ा जाता है। कई श्रद्धालु नाग दोष और जीवन की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए भी यहां पूजा-अर्चना करते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ मां के चरणों में सिर झुकाने वाले भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है।

समय के साथ मंदिर में कई आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। अब श्रद्धालु रोपवे के माध्यम से आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि आज भी कई भक्त पैदल चढ़ाई करना अधिक पुण्यदायी मानते हैं। वे "जय माता दी" के जयकारे लगाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ पर्वत की चढ़ाई करते हैं। यह यात्रा केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा भी मानी जाती है।

आज के आधुनिक समय में जहां इंसान तनाव, अकेलेपन और भौतिक इच्छाओं में उलझता जा रहा है, वहां मां मनसा देवी का यह मंदिर लोगों को आस्था और विश्वास की नई रोशनी देता है। यहां आने वाला हर भक्त अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करता है। कुछ लोग अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ आते हैं, तो कुछ अपने टूटे हुए मन को संभालने के लिए। लेकिन मां के दरबार से लौटते समय उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष दिखाई देता है।

मां मनसा देवी का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों और विश्वास का केंद्र है। यहां की हवा में भक्ति है, वातावरण में आध्यात्मिक शक्ति है और हर पत्थर में श्रद्धा की कहानी बसती है। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी इस मंदिर की महिमा कम नहीं हुई। मां के दरबार में आने वाला हर भक्त यही महसूस करता है कि सच्ची श्रद्धा के साथ मांगी गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां मनसा देवी अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देती हैं और उनके जीवन में आस्था का ऐसा दीप जला देती हैं, जो कभी बुझता नहीं।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

35 लाख+ यूजर्स और 6 लाख+ सारथियों के साथ 'भारत टैक्सी' बनी दुनिया की सबसे बड़ी मोबिलिटी कोऑपरेटिव

▶▶ भारत टैक्सी से जुड़े ड्राइवरों (सारथियों)की मासिक आय में 25% से 30% तक की वृद्धि, जबकि यात्रियों को मिल रहा है औसतन 15% सस्ता और पारदर्शी किराया

▶▶ 10,000+ सारथियों को सॉफ्ट स्किल्स और डिजिटल हैंडलिंग का मिला प्रोफेशनल प्रशिक्षण

▶▶ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस के साथ SOS इंटीग्रेशन

गांधीनगर : जब हम 'सहकारिता' शब्द सुनते हैं, तो अक्सर हमारे जेहन में अमूल की दूध क्रांति का चित्र उभरता है। लेकिन आज गुजरात की सड़कों पर एक नई डिजिटल क्रांति दौड़ रही है जिसका नाम है 'भारत टैक्सी'। यह सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के सपने को सच करते उन हजारों सारथियों की कहानी है, जो अब किसी कंपनी के कर्मचारी नहीं, बल्कि इस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के खुद मालिक हैं। 5 फरवरी को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई यह पहल, तकनीक और मानवीय गरिमा के संगम का दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है।

भारत टैक्सी के चेयरमैन और अमूल के एमडी जयेन मेहता इस बदलाव को एक बड़ी क्रांति के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार, "भारत टैक्सी ने ड्राइवर-ओन्ड मॉडल को धरातल पर उतारकर यह सुनिश्चित किया है कि राइड की 100% कमाई बिना किसी कटौती के सीधे ड्राइवर्स तक पहुँचे। आज यह दुनिया की सबसे बड़ी मोबिलिटी कोऑपरेटिव के रूप में उभरकर न केवल सारथियों की गरिमा बहाल कर रही है, बल्कि 'सहकार से समृद्धि' के विजन को वैश्विक स्तर पर एक नया बेंचमार्क दे रही है।"

कमीशन का 'खेल' खत्म, अब सारथी ही मालिक

मोबिलिटी सेक्टर में अब तक सारथियों की सबसे बड़ी त्रासदी भारी-भरकम कमीशन और अनिश्चित आय रही है। लेकिन 'भारत टैक्सी' ने इस पुराने ढर्रे को ध्वस्त कर दिया है। यहाँ कोई बिचौलिया या कॉर्पोरेट नहीं है, बल्कि सारथी ही इस कोऑपरेटिव के स्टेकहोल्डर्स हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद एक औसत सारथी की मासिक आय में 25% से 30% तक का उछाल आया है। यह आंकड़ा केवल कमाई नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की खुशहाली का दस्तावेज है जो अब पारंपरिक एग्रीगेटर मॉडल से बाहर निकल रहे हैं।

सारथियों के जीवन में आए इस बदलाव को प्रवीण ठाकोर के अनुभव से बखूबी समझा जा सकता है। वे बताते हैं, "अन्य कंपनियों के साथ काम करना अब फ़ायदेमंद नहीं रह गया था। लेकिन 'भारत टैक्सी' से जुड़ने के बाद हमें बेहतरीन रेट और रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। इस मॉडल से जुड़कर कोई भी सारथी अच्छी कमाई कर अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकता है।"

डायनेमिक प्राइसिंग' से मुक्तिः पारदर्शी सिस्टम से यात्रियों को मिल रही लगभग 15% तक की बचत

भारत टैक्सी केवल सारथियों की आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने 'पैसेंजर एक्सपीरियंस' को भी एक नया आयाम दिया है। जहाँ निजी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स में 'डायनेमिक प्राइसिंग' के कारण किराए में अनिश्चितता बनी रहती है, वहीं भारत टैक्सी ने किराया संरचना को स्थिर और पारदर्शी रखा है। इसका सीधा लाभ यात्रियों को मिल रहा है, जिन्हें औसतन 15% तक कम किराया देना पड़ रहा है।

यात्रियों की इस बचत और सारथियों की आज़ादी के इस 'विन-विन' मॉडल की ज़मीनी हकीकत बताते हुए ड्राइवर जनक बारोट कहते हैं, "यहाँ 'जीरो कमीशन' है और भुगतान सीधे हमारे खाते में आता है; हम खुद को इसका मालिक महसूस करते हैं। अन्य कंपनियों के 30/किमी के मुकाबले हम ग्राहकों से 17-18 का किफायती रेट ले रहे हैं, जो उनके लिए भी फायदेमंद है। भविष्य में संस्था के विस्तार के साथ ही हमें पेंशन और बीमा जैसी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।"

6 लाख+ सारथी और 35 लाख+ यूजर्स का बड़ा नेटवर्क, अब जल्द वडोदरा में भी शुरू होगी भारत टैक्सी

गुजरात में 1 लाख सहित देशभर में 6 लाख से अधिक सारथियों और 35 लाख+ ऐप डाउनलोड्स के साथ 'भारत टैक्सी' तेजी से एक मजबूत राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बन रही है। अहमदाबाद और सूरत में शानदार सफलता के बाद, अब वडोदरा कंपनी के विस्तार का अगला प्रमुख केंद्र है। अपनी जमीनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए कंपनी 'बिलो द लाइन' (BTL) रणनीति के तहत आईटी पार्क, हाउसिंग सोसायटी और एयरपोर्ट जैसे अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में सीधे यूजर्स से जुड़कर इसे एक जन-केंद्रित ब्रांड बना रही है।

इस बढ़ते नेटवर्क और आसान प्रक्रिया पर अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन के प्रेसिडेंट अजय कुमार गुप्ता कहते हैं, "ग्राहकों को यह बात बहुत आकर्षित करती है कि यह 'अपने भारत की कंपनी' है और इसमें सारथियों से कोई कमीशन नहीं लिया जाता। मेरी सभी सारथियों से अपील है कि वे इससे जुड़ें। इसकी प्रक्रिया इतनी आसान है कि ऐप पर खुद दस्तावेज़ सबमिट करने के महज़ 12 घंटों के भीतर अप्रूवल मिल जाता है।"

गुजरात में भारत टैक्सी को मिला राज्य पुलिस का 'सुरक्षा कवच' और इन्टीग्रेटेड ट्रान्ज़िट सिस्टम की सुविधा

सुरक्षा और तकनीक के बेजोड़ तालमेल का प्रमाण गुजरात पुलिस के साथ इसका सीधा SOS इंटीग्रेशन है, जो यात्रियों और सारथियों के लिए एक 'सुरक्षा कवच' की तरह काम करता है। इतना ही नहीं, सोमनाथ और द्वारकाधीश जैसे पावन तीर्थ स्थलों के लिए समर्पित रूट कनेक्टिविटी ने भारत टैक्सी को केवल शहरी परिवहन तक सीमित न रखकर, श्रद्धालुओं की आस्था और भरोसे का सारथी भी बना दिया है।

इतना ही नहीं, सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अब तक 10,000 से अधिक ड्राइवरों को डिजिटल लिटरेसी और सॉफ्ट स्किल्स का गहन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मेट्रो, GSRTC और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ इसके 'इन्टीग्रेटेड ट्रान्ज़िट सिस्टम' ने गुजरात में सफर को एक निर्बाध अनुभव में बदल दिया है।

अहमदाबाद मंडल पर व्यापक पर्यावरण जागरूकता अभियान,अहमदाबाद मंडल का महा-अभियानः 'विश्व पर्यावरण दिवस 2026' पर हरित और सतत रेल की ओर कदम

भारतीय रेलवे द्वारा "विश्व पर्यावरण दिवस 2026" के उपलक्ष्य में 15 मई 2026 से 5 जून 2026 तक देशव्यापी व्यापक पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में, पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सतत जीवनशैली (Sustainable Lifestyle) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों तथा रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रम एवं जनजागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।

इस तीन सप्ताह लंबे अभियान को मंडल द्वारा अलग-अलग चरणों में विभाजित कर बेहद योजनाबद्ध और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैः

हरित रेल परिचालन और "एक पेड़ माँ के नाम"

वर्तमान में चल रहे इस चरण में पर्यावरण को नया जीवन देने के लिए हरित आवरण (Green Cover) बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा हैः

वृहद वृक्षारोपणः माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मंडल भर में "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रेलवे कॉलोनियों, स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया और खाली भूखंडों को हरा-भरा बनाने और पार्कों के सुंदरीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सतत जीवनशैली गतिविधियांः ई-वेस्ट (E-Waste) प्रबंधन, कचरे के पुनर्चक्रण (Recycling) तथा पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली के तहत शारीरिक फिटनेस और आउटडोर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा रहा है।

OSOP का सहयोगः 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' (OSOP) योजना के तहत स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जा रहे कपड़े और जूट के थैलों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्लास्टिक बैग का विकल्प मिल सके।

प्रतियोगिताएं एवं निरीक्षणः रेल कर्मचारियों के बच्चों और यात्रियों के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विषय पर चित्रकला, निबंध लेखन एवं प्रश्नोत्तरी (Quiz) प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही, स्टेशनों पर ट्रेनों के बायो-टॉयलेट और अपशिष्ट निपटान प्रणालियों का अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।

अभियान का शुभारंभ एवं डिजिटल जागरूकता

अभियान के प्रथम चरण में संपूर्ण अहमदाबाद मंडल में औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके तहत डिजिटल इंडिया और पेपरलेस प्रणाली को बढ़ावा देते हुए बड़े पैमाने पर काम किया गयाः

डिजिटल आउटरीचः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर #MissionLiFE और WED 2026 थीम के तहत सघन अभियान चलाया गया।

यात्री संवेदीकरणः रेलवे स्टेशनों और कार्यालय परिसरों में जलवायु परिवर्तन, "सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना कहें" तथा पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली से जुड़े आकर्षक पोस्टर, बैनर और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित किए गए।

पेपरलेस यात्रा को बढ़ावाः यात्रियों को RailOne और अन्य ऑनलाइन ऐप के माध्यम से डिजिटल टिकटिंग अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया ताकि कागज की बचत की जा सके।

कार्यशालाएं एवं क्षमता निर्माणः रेलवे कर्मचारियों के लिए जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management) और पर्यावरण-अनुकूल कार्यप्रणाली पर विशेष कार्यशालाएं आयोजित की गईं। साथ ही यात्रियों को "अपनी पानी की बोतल साथ रखें" संदेश के तहत पुनः उपयोग योग्य बोतलों और कंटेनरों का उपयोग करने की शपथ दिलाई गई।

स्वच्छता, कचरा प्रबंधन एवं ऊर्जा संरक्षण के कड़े कदम

इस चरण के दौरान कचरे के उचित निपटान और ऊर्जा की भारी बचत के लिए अनुकरणीय कदम उठाए गएः

कचरा पृथक्करण (Waste Segregation): प्लेटफॉर्मों पर गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। स्थानीय समुदायों और स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOs) के समन्वय से स्टेशनों के आसपास स्वच्छता अभियान चलाए गए।

इको-फ्रेंडली कैटरिंगः IRCTC के सहयोग से वेंडिंग स्टॉलों और ट्रेनों में जैव-अवक्रमणीय (Biodegradable) एवं प्लास्टिक-मुक्त कटलरी के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया गया।

ऊर्जा संरक्षण की मिसाल (Energy Conservation): मंडल रेल प्रबंधक (DRM), अहमदाबाद के कुशल दिशा-निर्देशानुसार ऊर्जा संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए 19 मई 2026 को मंडल कार्यालय अहमदाबाद में सभी एयर कंडीशनर (AC) और लाइटें एक घंटे के लिए बंद रखी गईं। इसी प्रकार, 20 मई 2026 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक मंडल की सभी रेलवे कॉलोनियों में लाइटें बंद रखकर समाज को बिजली बचाने का एक बड़ा संदेश दिया गया।

प्लास्टिक उन्मूलन, रिसाइक्लिंग एवं नुक्कड़ नाटक

प्लास्टिक प्रदूषण को जड़ से खत्म करने के लिए अहमदाबाद मंडल द्वारा ज़मीनी स्तर पर कड़े प्रयास किए गएः

सख्त निगरानीः स्टेशनों पर लगी प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनों (PBCM) के सुचारू संचालन की समीक्षा की गई। स्टेशन वेंडर स्टॉलों पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक (SUP) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए विशेष फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा निगरानी रखी गई।

माइक्रोप्लास्टिक नियंत्रणः विक्रेताओं और पैंट्री कर्मचारियों को दूध, छाछ या अन्य खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग बैग को पूरी तरह से अलग न काटते हुए, आंशिक रूप से काटने (Partial Cutting) के लिए शिक्षित किया गया, ताकि कचरे के छोटे टुकड़े पर्यावरण में मिलकर माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण न फैलाएं।

सांस्कृतिक माध्यम से अलखः यात्रियों को जागरूक करने के लिए असारवा स्टेशन और ईएलएफ (ELF) वटवा में स्थानीय कलाकारों द्वारा पर्यावरण केंद्रित नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया, जिसे यात्रियों की भारी सराहना मिली। साथ ही जल पुनर्भरण (Water Recharging) केंद्रों का सघन निरीक्षण भी किया गया।

"भारतीय रेलवे द्वारा चलाया जा रहा यह 21 दिवसीय अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा की बचत और सतत विकास के प्रति जनसामान्य को जोड़ने का एक पावन जन-आंदोलन है। अहमदाबाद मंडल भविष्य में भी पर्यावरण के अनुकूल, कार्बन-न्यूट्रल और हरित रेल परिचालन के लिए पूरी तरह प्रतिज्ञाबद्ध है।" भारतीय रेलवे द्वारा यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, ऊर्जा संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति जनसामान्य में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

गोधरा में यार्ड इम्प्रूवमेंट का महत्पूर्ण इंफ्रा वर्क पूर्ण

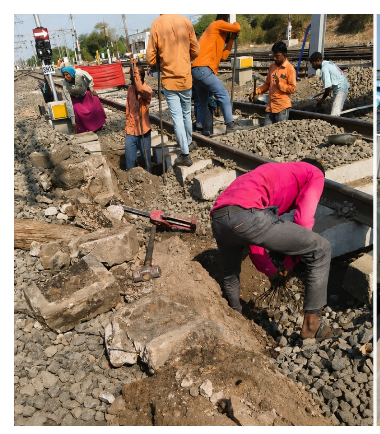

रेलवे अधोसंरचना को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा गोधरा यार्ड में दिनांक 25 मई, 2026 को व्यापक यार्ड इम्प्रूवमेंट एवं ड्रेनेज सुधार कार्य किए गए। इन कार्यों से परिचालन में संरक्षा, ट्रैक स्थिरता तथा रेल परिचालन की समग्र विश्वसनीयता में वृद्धि के साथ साथ गोधरा यार्ड में जल निकासी व्यवस्था में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गोधरा यार्ड में डाउन मेन लाइन पर ब्लॉक लेकर इस कार्य के अंतर्गत पॉइंट संख्या 121, 115, 109 एवं 106 पर व्यापक अनुरक्षण एवं नवीनीकरण कार्य किए गए, जिनमें कुल 350 पी एंड सी स्लीपरों का नवीनीकरण किया गया। साथ ही एमके-V ERC, लाइनर एवं रबर पैड के साथ सम्पूर्ण फिटिंग नवीनीकरण कार्य किया गया तथा सभी पॉइंट्स पर स्लीपर स्पेसिंग एवं स्लीपर स्क्वेरिंग कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

इंफ्रा के इस महत्पूर्ण कार्य में पुराने साधारण स्लीपरों के स्थान पर 391 वाइड बेस स्लीपरों से नवीनीकरण किया गया। 78 स्लीपरों का डीप स्क्रीनिंग कार्य के साथ नवीनीकरण किया गया, जिसमें 350 मिमी बैलास्ट कुशन सुनिश्चित किया गया।वाइड बेस स्लीपर सेक्शन में TSR कार्य के साथ सम्पूर्ण फिटिंग नवीनीकरण भी किया गया।

गोधरा यार्ड क्षेत्र में इन सुधार कार्यों से ट्रैक संरक्षा, रेल परिचालन की विश्वसनीयता, राइडिंग गुणवत्ता तथा जल निकासी व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा।

अहमदाबाद मण्डल पर मण्डल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति,की पाँचवी बैठक का आयोजन

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल में दिनांक 28.05.2026 को मण्डल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (DRUCC) की पाँचवी बैठक मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, अहमदाबाद में आयोजित की गई। बैठक के प्रारम्भ में मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिवादन करते हुए उनके-अपने क्षेत्रों से संबंधित सुझाव आमंत्रित किए।

अपने सम्बोधन में मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने बताया कि नलिया–वायोर के मध्य मालगाड़ी परिवहन सितंबर 2026 तक प्रारंभ करने की योजना है। उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय रेल का सबसे बड़ा 98 लाइनों वाला कोचिंग हब वटवा में विकसित किया जाएगा तथा वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का कार्य भी तीव्र गति से प्रगति पर है। इसके साथ ही सरखेज–धोलेरा सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना के बारे में भी विस्तृत जानकारी साझा की गई।

समिति के सचिव एवं वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक श्री अन्नू त्यागी ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अहमदाबाद मंडल में चल रही विभिन्न गतिविधियों एवं विकासात्मक परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मंडल की प्रमुख उपलब्धियों एवं विकास कार्यों पर प्रकाश डाला।

श्री त्यागी ने बताया कि अहमदाबाद, साबरमती एवं भुज स्टेशनों का मेजर रीडेवलपमेंट कार्य प्रगति पर है, जिनमें साबरमती एवं भुज स्टेशनों का कार्य उन्नत चरण में पहुँच चुका है। इसके अतिरिक्त मंडल के अन्य प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास "अमृत भारत स्टेशन योजना" के अंतर्गत किया जा रहा है।

अहमदाबाद मंडल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं विकास कार्य

▶▶ अहमदाबाद मंडल पश्चिम रेलवे का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला मंडल है।

▶▶ मंडल द्वारा 412 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस एवं यात्री गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 118 मूल गाड़ियां शामिल हैं।

▶▶ वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रतिदिन लगभग 1.1 लाख यात्रियों ने अहमदाबाद मंडल से यात्रा प्रारंभ की।

▶▶ मंडल ने पश्चिम रेलवे की कुल यात्री आय में 21% तथा माल लदान में 49% योगदान दिया।

▶▶ भारतीय रेलवे में अहमदाबाद मंडल माल लदान में 8वें तथा माल आय में 7वें स्थान पर रहा।

▶▶ मंडल द्वारा मुंद्रा पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट (कांडला) एवं टूना पोर्ट जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों को रेल कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।

▶▶ मंडल में 143 यात्री स्टेशन, 33 रेलवे फ्रेट टर्मिनल एवं 7 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कार्यरत हैं।

▶▶ स्टेशन पुनर्विकास एवं अमृत भारत स्टेशन योजना

▶▶ अहमदाबाद स्टेशन का 2379 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय पुनर्विकास कार्य तेजी से प्रगति पर है।

▶▶ साबरमती बीजी एवं साबरमती जंक्शन स्टेशन पुनर्विकास कार्य लगभग 73% तक पूर्ण हो चुका है।

▶▶ न्यू भुज स्टेशन पुनर्विकास कार्य 76% तक पूर्ण हो चुका है।

▶▶ अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मंडल के 16 स्टेशनों का विकास 515.03 करोड़ की लागत से किया जा रहा है।

▶▶ सामाखियाली स्टेशन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं जबकि कालोल, हिम्मतनगर, भचाऊ आदि स्टेशनों पर तेजी से कार्य जारी है।

नई ट्रेन सेवाएं एवं विशेष गाड़ियां

▶▶ ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की सुविधा हेतु कई विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया।

▶▶ भुज–दिल्ली एक्सप्रेस का नई ट्रेन सेवा का संचालन 22 मई 2026 को प्रारंभ हुआ है।

▶▶ उदयपुर सिटी–असारवा वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ 16 फरवरी 2026 को किया गया।

गौरवपूर्ण उपलब्धियां एवं माल व्यवसाय

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में खेड़ब्रह्मा–हिम्मतनगर सेक्शन राष्ट्र को समर्पित किया गया।

▶▶ मंडल ने स्टेनलेस स्टील कंटेनरों द्वारा औद्योगिक नमक लदान की अभिनव शुरुआत की।

▶▶ बेचराजी से ACT-1 ऑटोमोबाइल रेक लोड कर 264 वाहनों का परिवहन किया गया।

▶▶ उंझा से मिर्जा (असम) तक मसालों की पहली पार्सल रेक चलाई गई।

▶▶ लिन्च से जम्मू-कश्मीर तक दुग्ध उत्पादों की पहली कार्गो रेक भेजी गई।

▶▶ बैठक के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित रेल समस्याओं, ट्रेनों के ठहराव, ट्रेनों का विस्तार, ट्रेनों का स्टोपेज प्रदान करने, नई ट्रेन सेवा शुरू करने एवं अंडर ब्रिज और रोड ओवर ब्रिज बनाने तथा नई परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन तथा स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाएँ उपलब्ध कराने स्टेशन पर ठंडे पानी की समुचित व्यवस्था, साफ-सफाई जैसे महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए।

इस अवसर पर समिति के सदस्य एवं अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा और मण्डल के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे तथा बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया।

पांच साल बाद राजुभाई ठक्कर को संपत्ति का कब्जा मिल गया, अदालत में सच्चाई की जीत हुई

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

सूरत शहर में दुर्घटना निवारण केंद्र के प्रमुख राजुभाई सी. ठक्कर, जो सूरत जिला नगर, सलाबतपुरा, बालाभाई स्ट्रीट, वार्ड नंबर 3, नोट नंबर 2241 में अपना व्यवसाय चलाते हैं, सेठ बालाभाई गोपालभाई धार्मिक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, सत्यनारायण मंदिर की संपत्ति का प्रबंधन कर रहे हैं। उक्त संपत्ति का पिछला हिस्सा पिपर्डी स्ट्रीट पर स्थित है, जहां वे एयरलाइट कॉर्पोरेशन और एयरलाइट डेकोरेशन के नाम से खिड़की के पर्दे बनाने और बेचने का व्यवसाय करते थे। मई 2021 में, सत्यनारायण मंदिर के प्रबंध न्यासी, संदीप गिरीशचंद्र पटेल ने पुलिस की मिलीभगत से उक्त स्थान पर चोरी और लूटपाट की और अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इस संबंध में, राजुभाई सी. ठक्कर ने 25/05/2021 को सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके 10 दिन बाद तत्कालीन निजी जांच अधिकारी एम.वी. किकानी और पुलिस जांच अधिकारी ने... एस.जी. चौहान ने राजूभाई सी. ठक्कर के खिलाफ झूठी एफआईआर में चोर को शिकायतकर्ता और शिकायतकर्ता को आरोपी बना दिया। इस मामले में मेरी शिकायत वर्तमान में अदालत में लंबित है। इस मामले में हेल्पलाइन 14449 पर पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच पुलिस आयुक्त कार्यालय के इको सेल में चल रही है। इसके अलावा, राजूभाई सी. ठक्कर ने केस संख्या 1/2021 में कब्जे के संबंध में शिकायत दर्ज कराई और स्वयं वकील के रूप में मुकदमा लड़ा। तत्कालीन कतरगाम मामलातदार हुड साहब ने 8 जनवरी 2024 को राजूभाई सी. ठक्कर के पक्ष में फैसला सुनाया। समावाला सत्यनारायण मंदिर के ट्रस्टी संदीप गिरीशचंद्र पटेल ने केस संख्या 10/2024 से जिला न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की। इस पुनरीक्षण याचिका में भी राजूभाई ठक्कर ने स्वयं वकील के रूप में पैरवी की। जिला न्यायालय के 12वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री अमितकुमार नरेंद्रभाई दवे साहब ने 1/10/2024 को समावाला ट्रस्टियों की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। इसके बाद समावाला ने फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया। राजुभाई सी. भी पक्षकार (वकील) के रूप में उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए और उन्होंने क्रॉसिंग पर साक्षात्कार दिया। चूंकि ठक्कर अब उपस्थित नहीं थे, इसलिए वादी ने 12/02/2026 को श्री आर. मेंगड़े साहब की अदालत से उच्च न्यायालय में अपनी याचिका वापस ले ली। उपरोक्त मामले के बाद, 16/05/2026 को कतरगाम मामलतदारश्री ने राजुभाई ठक्कर को कब्जा सौंपने का आदेश दिया। इसके कार्यान्वयन के लिए सूरत के अतिरिक्त कलेक्टर श्री और मजिस्ट्रेट साहब श्री रबारी साहब ने इसे अपने समक्ष प्रस्तुत किया। 21/05/2026 को, कतरगाम मामलतदार दिनेशभाई गामित के मार्गदर्शन में, कतरगाम सर्कल ऑफिसर श्री क्रुणालभाई पटेल नाओ सलाबतपुरा सत्यनारायण मंदिर स्थल पर, निजी जांच अधिकारी श्री आर. ए. जडेजा साहब के मार्गदर्शन में, पुलिस काफिले और पुलिस व्यवस्था के साथ, उक्त स्थान का कब्जा राजुभाई सी. ठक्कर को सौंप दिया गया। इस प्रकार सत्य की विजय हुई और राजुभाई ठक्कर ने पांच साल पुराने सदरहु मामले में सफलता प्राप्त की।

सूरत के नए सिविल अस्पताल में सुविधाओं की कमी के कारण गरीब मरीजों को इलाज के लिए भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

सूरत का नया सिविल अस्पताल दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए यहां आते हैं। सूरत शहर में देशभर के लोग रहते हैं। इसी वजह से अगर उन्हें या उनके रिश्तेदारों को इलाज की जरूरत पड़ती है, तो वे सूरत के इस अस्पताल से संपर्क करते हैं। सिविल अस्पताल में कई तरह के ऑपरेशन होते हैं। लेकिन इतने सालों से मौजूद होने के बावजूद सरकार यहां हृदय रोग, गुर्दे, यकृत और मस्तिष्क रोगों का इलाज उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। गुर्दा अस्पताल की इमारत करोड़ों रुपये की लागत से बनी है, लेकिन कर्मचारियों और उपकरणों की कमी के कारण यह धूल फांक रही है। और अस्पताल आने वाले मरीजों को हृदय, गुर्दे, यकृत और मस्तिष्क के इलाज के लिए अहमदाबाद या मुंबई तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। आर्थिक रूप से सक्षम मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। वहीं गरीब परिवारों के मरीज मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं। अगर सूरत के सिविल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग, गुर्दे, यकृत और मस्तिष्क रोगों का इलाज उपलब्ध कराया जाए, तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भी इसका लाभ उठा सकेंगे। सूरत के सिविल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को इस दिशा में सोचना चाहिए। सूरत शहर के तीन सांसदों और लगभग 12 विधायकों को सिविल अस्पताल को इस तरह का उच्च स्तरीय उपचार प्रदान करने के बारे में सोचना चाहिए। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि नए सिविल अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर गरीब मरीजों को तकलीफ झेलनी पड़े, जबकि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री सूरत से ही हों? इस नए सिविल अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए बाईपास सर्जरी के उपकरणों की कमी, आधुनिक मशीनों का अभाव और डॉक्टरों की भी कमी के कारण, जाति-धर्म के भेदभाव के बिना, आदिवासी और दलित समेत गरीब मरीज इतनी दूर से आते हैं और उन्हें इलाज के लिए दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती हैं? सरकार दवाइयों और उपकरणों के लिए करोड़ों रुपये का अनुदान देती है, फिर भी मरीजों को अच्छी हालत में स्ट्रेचर या व्हीलचेयर नहीं मिलतीं। शर्म की बात है

कि मरीजों को वार्ड तक ले जाने के लिए उनके रिश्तेदारों को खुद स्ट्रेचर खींचकर ले जाना पड़ता है। मरीजों को दिए जाने वाले गद्दे और चादरें भी बदबूदार होती हैं। यहां तक कि मरीजों के खाने के बर्तन भी अलमारियों में रखे रहते हैं। संक्षेप में कहें तो, अस्पताल के प्रशासन के लिए अच्छे अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है। अगर स्वास्थ्य मंत्री साल में सिर्फ एक बार ऐसे अधिकारी का तबादला कर दें, तो प्रशासन में सुधार नहीं होगा।

एक तरफ जहां ठेकेदार अपने चहेतों को नए भवन निर्माण के ठेके देकर अपनी जेबें भर रहे हैं, वहीं भविष्य में बनने वाले उन भवनों का क्या उपयोग है जो डॉक्टरों और मशीनरी की कमी के कारण खंडहर में बदल जाते हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक बन जाते हैं?

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गांधीनगर जिले में 340 करोड़ रुपए के 84 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

- 2029 तक गांधीनगर जिले के प्रत्येक गांव में एक-एक पुस्तकालय और उद्यान के साथ ही सुंदर मनोरंजन स्थल उपलब्ध होंगे
- आज 'गुजरात विकास मॉडल' कश्मीर से कन्याकुमारी और सोमनाथ से गंगासागर तक पूरे देश में स्वीकृत
- राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार विदेशी घुसपैठियों को चुन-चुनकर देश से बाहर निकालने को प्रतिबद्ध
- 1857 के विद्रोह को 'स्वतंत्रता संग्राम' का नाम देने वाले वीर सावरकर ने सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता निवारण और दलितों के लिए पतित पावन मंदिर के निर्माण जैसे क्रांतिकारी कार्य किए

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- गांधीनगर को 'हरित लोकसभा' बनाने के लिए 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य
- गांधीनगर में बनेगी देश की सबसे बड़ी और आधुनिक 'नमो सेंट्रल लाइब्रेरी' : बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
- केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में गांधीनगर को देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध

कलोल और गांधीनगर उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जीयूडीए, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों की भेंट : निजी कंपनियों के सीएसआर फंड से ग्रामीण पुस्तकालयों का निर्माण और तालाबों का सौंदर्यीकरण

गांधीनगर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज गांधीनगर जिले के सोनीपुर गांव में कलोल और गांधीनगर उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 340 करोड़ रुपए के 84 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम से पूर्व दोनों महानुभावों ने पौधरोपण भी किया।

आज आयोजित इन कार्यक्रमों में सरकारी विभागों के साथ ही निजी कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड के सहयोग से पंचायत तथा सड़क एवं भवन विभाग के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसके अलावा, रेलवे के अंडरब्रिज के कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य में बह रही विकास की गंगा का श्रेय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को देते हुए कहा कि गांधीनगर संसदीय क्षेत्र को देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ विकास कार्यों की बौछार शुरू हो चुकी है। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आज 340 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इसके साथ ही, पिछले 10 दिनों में करीब 1200 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य शुरू किए गए हैं। जो दर्शाता है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा उद्योग समूहों के सीएसआर फंड की सहायता से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास तेज किए गए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर और सुविधासंपन्न बनाने के विजन का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केवल वित्तीय कोष ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हर गांव को आत्मनिर्भर बनाना और सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित करना सरकार की प्राथमिकता है। हर नागरिक सम्मानपूर्वक जीवन जिए, इसके लिए गांवों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। अधिक से अधिक युवाओं में पठन-पाठन की आदत विकसित हो, इसके लिए ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की गई है, जिसे गांधीनगर की लाइब्रेरी के साथ जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, वर्ष 2029 तक गांधीनगर के हर गांव में एक-एक पुस्तकालय और उद्यान के साथ ही सुंदर मनोरंजन स्थल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विकास-उन्मुख नीतियों को ध्यान में रखकर ही नागरिकों ने उन्हें सत्ता की कमान सौंपी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जो 'गुजरात विकास मॉडल' दिया था, वह आज कश्मीर से कन्याकुमारी और सोमनाथ से गंगासागर तक पूरे देश में स्वीकृत हो गया है।

हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। जहां पहले की सरकार के शासन में रोजाना घुसपैठ होती थी, वहां अब घुसपैठिए स्वयं अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं। सरकार ने डिटेंशन सेंटर भी बनाए हैं। जो घुसपैठिए अपनी मर्जी से देश छोड़ेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और सरकार उन्हें मदद भी करेगी।

श्री शाह ने दृढ़तापूर्वक कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर घुसपैठियों को चुन-चुनकर देश से बाहर निकालने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो असामान्य कारणों से पूरे देश में हो रहे डेमोग्राफिक परिवर्तनों की जांच करके एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आवश्यकता पड़ने पर कठोर कानून भी बनाए जाएंगे।

वीर सावरकर जी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए श्री शाह ने कहा कि वे एक ऐसे राष्ट्रभक्त थे, जिन्हें देश का हर बालक आदरपूर्वक 'वीर सावरकर' के नाम से जानता है। आजादी के आंदोलन के दौरान उन्हें दोहरी उम्रकैद की सजा हुई थी। कालापानी की सजा के दौरान जेल की दीवारों पर अपने लहू से कविताएं लिखने वाले और 1857 के विद्रोह को 'स्वतंत्रता संग्राम' का नाम देने वाले सावरकर जी ने सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता निवारण और दलितों के लिए पतित पावन मंदिर का निर्माण जैसे क्रांतिकारी कार्य किए थे।

अंत में, उन्होंने एक बार फिर गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र को देश का सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्र बनाने का इरादा व्यक्त किया और सभी नागरिकों से इस विकास यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गांधीनगर संसदीय क्षेत्र को देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनाने के लक्ष्य के साथ आज गांधीनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र और कलोल तहसील में 340 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सोनीपुर तालाब का शिलान्यास किया गया।

ग्रामीण नागरिकों की सुख-सुविधा में वृद्धि करने वाली विभिन्न परियोजनाएं जनता को समर्पित की गईं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा 10 दिन पहले ही 620 करोड़ रुपए के कार्यों की मंजूरी देने के बाद, उनकी ओर से गांधीनगर जिले के नागरिकों को यह लगातार दूसरी बड़ी सौगात मिली है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा-पानी की विरासत देने के लिए गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 1 करोड़ पौधे लगाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आगामी समय में डिजिटल और सांस्कृतिक साक्षरता को ध्यान में रखकर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, जिला प्रशासन, सीएसआर फंड और दानदाताओं के सहयोग से 20 गांवों में लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना है, जिसके अंतर्गत आज तीन गांवों में महान साहित्यकारों कवि नर्मद, आद्यकवि दलपतराम और गोवर्धनराम त्रिपाठी के नाम पर आधुनिक पुस्तकालय शुरू किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि गांधीनगर में देश की सबसे बड़ी और आधुनिक 'नमो सेंट्रल लाइब्रेरी' बनाने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, गुजरात में पिछले दो वर्षों में 135 नए तहसील पुस्तकालयों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि जल्द ही गांव में नए स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण माताओं और बहनों को स्थानीय स्तर पर ही चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य केवल भौतिक संरचनाएं खड़ी करना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में 'ईज ऑफ लिविंग' यानी जीवन सुगमता को बेहतर बनाकर वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करना है।

इस अवसर पर गांधीनगर उत्तर की विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल ने स्वागत भाषण में आंकड़ों के साथ राज्य सरकार के विभिन्न विकास कार्यों की रूपरेखा पेश की।

कार्यक्रम में गांधीनगर दक्षिण के विधायक श्री अल्पेश ठाकोर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेशभाई पटेल, जिला कलेक्टर श्री रवींद्र खटाले, जिला विकास अधिकारी श्री बी.जे. पटेल, सोनीपुर गांव के सरपंच और पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

क्षेत्रीय दलों की राजनीति पर आर्थिक संकट की छाया, कमाई आधी लेकिन खर्च लगातार बढ़ता गया

नई दिल्ली। देश की क्षेत्रीय राजनीति को लेकर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता, चुनावी खर्च और आर्थिक प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनावी सुधारों पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ताजा रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि देश के प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की आय में पिछले एक साल के दौरान भारी गिरावट दर्ज की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि कमाई घटने के बावजूद इन दलों के खर्चों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि कई पार्टियों ने अपनी घोषित आय से कहीं अधिक राशि खर्च कर दी। रिपोर्ट ने यह संकेत दिया है कि क्षेत्रीय राजनीति की आर्थिक संरचना अब गंभीर असंतुलन की स्थिति में पहुंचती दिखाई दे रही है।

एडीआर ने भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध 36 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों के प्रमाणित ऑडिट खातों का विस्तृत अध्ययन किया। इस अध्ययन में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन क्षेत्रीय दलों की कुल आय 2,463.17 करोड़ रुपये थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह घटकर केवल 1,192.94 करोड़ रुपये रह गई। यानी एक ही साल में क्षेत्रीय दलों की आय में 51.57 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई।

यह गिरावट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति की आर्थिक स्थिति में आए बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी चंदे के स्रोतों में कमी, राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव और बड़े राष्ट्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव के कारण क्षेत्रीय दलों की वित्तीय ताकत कमजोर होती जा रही है। लेकिन इस पूरी तस्वीर का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि कमाई घटने के बावजूद खर्च लगातार बढ़ता गया।

रिपोर्ट के अनुसार इन 36 क्षेत्रीय दलों का कुल घोषित व्यय 1,433.07 करोड़ रुपये रहा, जो उनकी कुल आय से लगभग 240.12 करोड़ रुपये अधिक है। यानी राजनीतिक दलों ने अपनी कमाई से करीब 20 प्रतिशत ज्यादा खर्च किया।

इस वित्तीय असंतुलन ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर जब आय कम हो रही है तो राजनीतिक दल इतने बड़े खर्च कैसे उठा रहे हैं? रिपोर्ट बताती है कि 36 में से 21 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी घोषित वार्षिक आय से कहीं अधिक राशि खर्च की। इसका मतलब साफ है कि ये दल या तो अपने पुराने वित्तीय भंडार, आरक्षित निधि या अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों के सहारे राजनीतिक गतिविधियां चला रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार चुनावी राजनीति में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बड़े स्तर पर प्रचार अभियान, डिजिटल कैंपेन, संगठन विस्तार और लगातार होने वाले चुनावों ने क्षेत्रीय दलों के खर्च को बहुत बढ़ा दिया है। कई दलों के लिए राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने की लड़ाई अब आर्थिक दबाव में बदलती जा रही है।

रिपोर्ट ने क्षेत्रीय राजनीति में आर्थिक असमानता की भी तस्वीर पेश की है। आंकड़ों के अनुसार कुल 36 दलों में से केवल शीर्ष पांच राजनीतिक दलों के पास ही अधिकांश संसाधनों का नियंत्रण है। इन पांच दलों की हिस्सेदारी कुल क्षेत्रीय आय में लगभग 69 प्रतिशत है, जबकि कुल खर्च में इनका हिस्सा 77 प्रतिशत से भी अधिक है। इसका अर्थ है कि क्षेत्रीय राजनीति में आर्थिक ताकत कुछ चुनिंदा दलों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है, जबकि छोटे दल संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट का एक और गंभीर पहलू राजनीतिक दलों द्वारा वित्तीय पारदर्शिता के नियमों की अनदेखी है। देश में कुल 67 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार सभी दलों को वित्तीय वर्ष 2024-25 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करनी थी। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार 31 दल ऐसे हैं जिन्होंने निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के 207 दिन बाद तक भी अपने खातों का विवरण जमा नहीं कराया।

इन डिफॉल्टर दलों में कई बड़े और प्रभावशाली नाम शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), शिवसेना, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे प्रमुख क्षेत्रीय दलों ने भी समय पर अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक केवल 15 दलों ने तय समय सीमा के भीतर अपने ऑडिट खाते जमा किए, जबकि 21 दलों ने 2 दिन से लेकर 96 दिनों की देरी से रिपोर्ट सौंपी। इससे राजनीतिक दलों की वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक हैं और ऐसे में उनके वित्तीय लेनदेन पूरी तरह पारदर्शी होने चाहिए। लेकिन लगातार सामने आ रही देरी और असंतुलित खर्च यह संकेत देते हैं कि राजनीतिक फंडिंग व्यवस्था में अभी भी कई खामियां मौजूद हैं।

इंजीनियरिंग वर्कशॉप साबरमती में 'भगवद गीता' के ज्ञान से कार्यस्थल के तनाव प्रबंधन पर विशेष सत्र आयोजित

रेल कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और प्रभावी तनाव प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा 28 मई 2026 को साबरमती स्थित इंजीनियरिंग वर्कशॉप में "परसीव्ड स्ट्रेस एंड कोपिंग विद द हेल्प ऑफ भगवद गीता" (तनाव और भगवद गीता की सहायता से उसका सामना करना) विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया।

रेलवे संचालन और इंजीनियरिंग के अत्यधिक दबाव वाले माहौल में मानसिक लचीलापन और संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। इसी महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अहमदाबाद मंडल के अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (ACMS/A&H) डॉ. मनोजकुमार देव द्वारा एक संवादात्मक (इंटरैक्टिव) व्याख्यान दिया गया। इस कार्यशाला में लगभग 30 वरिष्ठ अधीनस्थों और अधिकारियों ने भाग लिया।

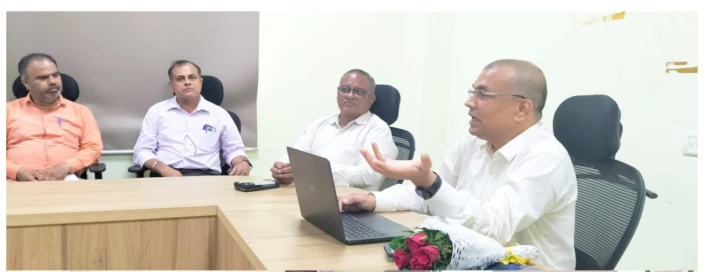

सत्र के दौरान, डॉ. देव ने तनाव से जुड़े आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और भगवद गीता के व्यावहारिक एवं प्राचीन ज्ञान के बीच के अंतर को बेहद सुगमता से पाटा। विशिष्ट श्लोकों का संदर्भ देते हुए, उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि कैसे ये शिक्षाएं रेल कर्मियों को कार्यस्थल के दबाव को देखने के नजरिए में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकती हैं।

कार्यशाला के मुख्य बिंदुः

- व्यावहारिक रणनीतियाँः प्रतिभागियों को दैनिक व्यावसायिक चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक तरीकों से अवगत कराया गया।
- मानसिक दृढ़ताः गंभीर रेलवे संचालन के दौरान मानसिक शांति और स्पष्टता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
- तनाव प्रबंधन का समग्र दृष्टिकोणः कार्यस्थल की आधुनिक चुनौतियों और तनाव को दूर करने के लिए पारंपरिक ज्ञान का समावेश।

यह पहल अहमदाबाद मंडल की अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के समग्र स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंडल द्वारा तकनीकी दक्षता के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य एवं आंतरिक सशक्तिकरण पर भी विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि कर्मचारी अधिक प्रभावी एवं समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें।

सरखेज-धोलेरा नई सेमी हाई स्पीड रेलवे ब्रॉड गेज डबल लाइन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु बैठक आयोजित

पश्चिम रेलवे अहमदाबाद की सर्वे एवं निर्माण संस्था ने आज (28.05.2026) सरखेज-धोलेरा नई सेमी हाई स्पीड रेलवे ब्रॉड गेज डबल लाइन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के विषय में इच्छुक बीडर्स के साथ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में एक बैठक आयोजित कीI पश्चिम रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस प्रोजेक्ट में चीफ इंजीनियर कमलेश कुमार, चीफ इलेक्टिकल इंजीनियर आर डी मीना, Dy CSTE रतन बासु व निर्माण विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मीटिंग की शुरुआत में प्रशांत सिंह, डिप्टी चीफ इंजीनियर ने पॉवर पॉइंट के माध्यम से प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ कियाI प्रोजेक्ट की निर्माण निविदा में रुचि रखने वाले सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा S & T (सिग्नल एवं दूरसंचार) क्षेत्रों की 20 से अधिक फर्मों ने भागेदारी की। जिसमें लार्सेन & टुब्रो, अफ्कोन्स इन्फ्रा, KPTL, HOG प्रोजेक्ट,

मिराल इन्फ्रा, खोडल कारपोरेशन, गंगा कंस्ट्रक्शन, नीलकंठ इन्फ्रा, सुभाष इन्फ्रा आदि फर्मों के प्रतिनिधियों ने प्रोजेक्ट कार्यान्वयन को बेहतर करने के लिये अपने- अपने सुझाव रखेI

बैठक में परियोजना के कार्यान्वयन, पैकेजिंग एवं तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अंतर्गत सिविल, ट्रेक, ट्रैक्शन व S&T के टेंडर व इंटरफ़ेस कार्यों, डिज़ाइन डिटेल्स के कांट्रेक्ट जैसे विषय पर चर्चा की गईI इसके अलावा कई फर्मों ने वर्चुअल माध्यम से से भी भगीदारी कीI इस दौरान पश्चिम रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) प्रदीप गुप्ता ने बताया इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य परियोजना का सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन करना हैI इच्छुक बीडर्स के सुझावों पर विचार करने के उपरांत प्रोजेक्ट कार्यान्वयन हेतु EPC टेंडर फ्लोट (float) किया जायेगाI करीब 134 किलोमीटर लंबी यह नई दोहरी रेल लाइन अहमदाबाद, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR), आगामी धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (National Maritime Heritage Complex) को अत्याधुनिक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। परियोजना की डिज़ाइन गति 220 किमी प्रति घंटा तथा परिचालन गति 200 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। कॉरिडोर पर कुल 11 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। परियोजना के अंतर्गत 3 मेगा पुल, 74 किलोमीटर वायाडक्ट, 39 रोड अंडर ब्रिज तथा 2 रेल ओवर रेल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। कुल ट्रैक लंबाई लगभग 293 किलोमीटर होगी। परियोजना को अगले 4 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लगभग 20,667 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी तकनीक आधारित सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना होगी, जिस पर भविष्य में नमो भारत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

यह परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना तथा भारत की लॉजिस्टिक दक्षता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। यह कॉरिडोर गुजरात को आधुनिक, हरित एवं उच्च गति परिवहन अवसंरचना के नए युग में प्रवेश कराने वाली ऐतिहासिक पहल सिद्ध होगा।

सोना वायदा 1857 रुपये और चांदी वायदा 4462 रुपये लुढ़काः क्रूड ऑयल वायदा में 222 रुपये का ऊछाल

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 79116.82 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 4897.71 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 74219.11 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 455.04 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 3602.17 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 155627 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 155651 रुपये और नीचे में 153551 रुपये पर पहुंचकर, 155627 रुपये के पिछले बंद के सामने 1857 रुपये या 1.19 फीसदी घटकर 153770 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी मई वायदा 975 रुपये या 0.78 फीसदी लुढ़ककर 123316 रुपये प्रति 8 ग्राम बोला गया। गोल्ड-पेटल मई वायदा 105 रुपये या 0.67 फीसदी लुढ़ककर 15515 रुपये प्रति 1 ग्राम बोला गया। सोना-मिनी जून वायदा सत्र के आरंभ में 153768 रुपये के भाव पर खूलकर, 157751 रुपये के दिन के उच्च और 153149 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1935 रुपये या 1.25 फीसदी लुढ़ककर 153326 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 154691 रुपये के भाव पर खूलकर, 155240 रुपये के दिन के उच्च और 153402 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 155240 रुपये के पिछले बंद के सामने 1589 रुपये या 1.02 फीसदी लुढ़ककर 153651 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा 261561 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 262389 रुपये और नीचे में 261013 रुपये पर पहुंचकर, 266212 रुपये के पिछले बंद के सामने 4462 रुपये या 1.68 फीसदी घटकर 261750 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 4576 रुपये या 1.69 फीसदी औंधकर 266101 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 4578 रुपये या 1.69 फीसदी की गिरावट के साथ 266141 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

मेटल वर्ग में 422.13 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 4.5 रुपये या 0.34 फीसदी की मजबूती के साथ 1323.55 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि जस्ता मई वायदा 1.45 रुपये या 0.39 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 371.1 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम जून वायदा 1.4 रुपये या 0.36 फीसदी की तेजी के संग 385.15 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि सीसा मई वायदा 15 पैसे या 0.07 फीसदी की नरमी के साथ 204 रुपये प्रति किलो बोला गया। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 814.29 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जून वायदा 8838 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 8900 रुपये और नीचे में 8703 रुपये पर पहुंचकर, 222 रुपये या 2.58 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 8822 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जून वायदा 219 रुपये या 2.55 फीसदी की बढ़त के साथ 8821 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस जून वायदा 298.6 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 300.8 रुपये और नीचे में 297 रुपये पर पहुंचकर, 301.3 रुपये के पिछले बंद के सामने 1.5 रुपये या 0.5 फीसदी घटकर 299.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जून वायदा 1.5 रुपये या 0.5 फीसदी गिरकर 299.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 2517.11 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 1085.06 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 315.02 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 49.58 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 0.93 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 56.59 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 417.37 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 393.47 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9770 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 67244 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 20437 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 329474 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 48060 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 10826 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 27993 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 92885 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 15485 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 21278 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जून 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 33.9 रुपये की बढ़त के साथ 173.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जून 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 65 पैसे की नरमी के साथ 16.25 रुपये हुआ।

सोना जून 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 94.5 रुपये की गिरावट के साथ 490 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जून 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 457 रुपये की गिरावट के साथ 2410 रुपये हुआ। तांबा जून 1400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 67 पैसे के सुधार के साथ 14.13 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जून 7500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 27.2 रुपये की गिरावट के साथ 69 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जून 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 45 पैसे के सुधार के साथ 16.15 रुपये हुआ। सोना जून 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 295.5 रुपये की बढ़त के साथ 972.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जून 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 228.5 रुपये की बढ़त के साथ 607.5 रुपये हुआ। तांबा जून 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 74 पैसे की नरमी के साथ 13.2 रुपये हुआ।

कमोडिटी वायदाओं में 4897.71 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 74219.11 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 3602.17 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार